

वैश्वीकरण का भारतीय युवाओं पर सामाजिक- आर्थिक प्रभाव

डॉ ओमप्रकाश शर्मा

सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग

शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय

सवाई माधोपुर (राजस्थान)

सार

वैश्वीकरण वैश्विक देशों को विदेशी संबंधों, कूटनीति, व्यापार, वित्त, शासन, नियम और विनियमन के करीब लाना है, जिससे दुनिया भर के देशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं में परस्पर निर्भरता बढ़ती है, दुनिया में यूडीसी (अविकसित देश) और विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, हम विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक ग्रामीण क्षेत्र पा सकते हैं। इसके अलावा भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश राजनीतिक संबंधों, आर्थिक संबंधों, सामाजिक और वैचारिक, निर्यात और आयात संबंधों द्वारा एक-दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से पूंजी के प्रवाह में भारी वृद्धि और विश्व व्यापार और संबंधों का तेजी से विकास। एक या दूसरे तरीके से, दुनिया भर के देश एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) और विभिन्न देशों के नागरिकों और एफपीआई से एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो संबंध) के प्रभाव ने भारत को विदेशी मुद्रा दरों, भुगतान संतुलन संतुलन पर अधिक निर्भर बना दिया है, लेकिन वैश्वीकरण ने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को भी प्रभावित किया है जहाँ ग्रामीण उद्यमियों को विदेशी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों, नवाचारों की कमी से प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शोध पत्र का अध्ययन यूडीसी में ग्रामीण उद्यमियों द्वारा सामना किए जाने वाले निवेश, बाधाओं या भारत में ग्रामीण उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की व्याख्या करता है। वैश्वीकरण कभी-कभी अच्छे सामाजिक-आर्थिक संबंधों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और देश में खराब सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है।

मूल शब्द: सामाजिक आर्थिक, वैश्वीकरण।

परिचय

भारत के पास मानव शक्ति, अच्छे विदेशी संबंधों के साथ कूटनीति में बहुत बड़ा लाभ है, लेकिन अभी भी 55% से अधिक भारतीय जनसंख्या ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहती है, जहां वैश्वीकरण ने ग्रामीण व्यवसायी और ग्रामीण निवेशकों को वैश्वीकरण के आधुनिक युग में अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। भारत दुनिया का 7 वां सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र के विकास में अधिक पूर्ण लाभ है, उदाहरण के लिए: बैंकिंग और शिक्षा, शैक्षिक सेवाएं और आतिथ्य, लेकिन हमने भारत में इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारे विदेशी निवेश वाले अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश), एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) देखे हैं, उदाहरण के लिए: गुजरात और महाराष्ट्र दुनिया भर में निवेश आकर्षित करने के लिए पसंदीदा गंतव्य हैं, यहां तक कि बेंगलूर, हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में जहां ग्रामीण उद्यमी गांवों और छोटे शहरों में प्रमुख निवेशक हैं। "विश्व

बैंक की रिपोर्ट" के आंकड़ों के अनुसार, 2019-2020 में भारत में मौजूद कुल जनसंख्या का प्रतिशत 65.07% बताया गया था, इसलिए भारत को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निवेश करना होगा। भारत एशिया और दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, दुनिया की अधिकांश अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में इंटरनेट नहीं है, यहां तक कि अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के अधिकांश संसाधनों को MNC's (बहु राष्ट्रीय कंपनियों) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनमें अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों के निवेशकों जैसे विकसित देशों द्वारा निवेश किया जाता है, इसलिए ग्रामीण उद्यमियों को उनसे भारी प्रतिस्पर्धा और बाजार की अनम्यता का सामना करना पड़ सकता है।

उद्देश्य

1. सामाजिक आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना।
2. वैश्वीकरण का अध्ययन करना।

वैश्वीकरण के बारे में युवाओं की प्रतिक्रिया :

अपने व्यापक अर्थ में, वैश्वीकरण का उद्देश्य दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों की सीमा का विस्तार करना है। जैसा कि एंथनी गिडेंस सुझाव देते हैं, "वैश्वीकरण को वैश्विक सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूरदराज के क्षेत्रों को इस तरह से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं सैकड़ों मील दूर होने वाली घटनाओं से प्रभावित होती हैं और इसके विपरीत।" इस संदर्भ में, दुनिया भर के समाजों का बढ़ता आर्थिक और सांस्कृतिक विश्वास दिलचस्प है। क्योंकि इसमें कई क्षेत्रों और स्तरों पर सहयोग शामिल है, इसलिए वैश्वीकरण को एक अवधारणा के रूप में सोचना लगभग असंभव है। जॉन एलन और डोरेन मैसी का तर्क है कि "वैश्विक व्यापार" का अधिकांश हिस्सा संचार, वित्त और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में होता है।

हालांकि, युवा संबंधों और वैश्वीकरण के किसी भी विश्लेषण में, दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, यह सोचने की प्रवृत्ति है कि वैश्वीकरण के प्रभाव अप्रतिरोध्य हैं, और वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा युवा लोग सक्रिय रूप से बातचीत करने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, वही और उतना ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि युवा लोगों से जुड़े ज्ञान, परिभाषाएँ और अवधारणाएँ वैश्वीकरण से जुड़ी अवधारणाओं जितनी ही जटिल और चुनौतीपूर्ण हैं। युवा लोगों में मौजूद अंतर, साथ ही युवा अनुभव के विभिन्न पहलुओं के महत्व के बारे में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ, इसकी वर्तमान स्थिति का लक्षित मूल्यांकन करना मुश्किल बनाती हैं। एक और खतरा यह है कि सामाजिक वैज्ञानिकों का समस्या-समाधान दृष्टिकोण वास्तव में युवा लोगों के पूर्वाग्रह और बीमारी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकता है और उसे बढ़ा सकता है।

युवा लोग सामाजिक परिवर्तन की गति या दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में उनकी राय होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उनके एकीकरण और भागीदारी को सुगम बनाने के लिए ऊपर वर्णित संभावित सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझना आवश्यक है। इस संदर्भ में, निम्नलिखित बातें शिक्षाप्रद हो सकती हैं: "युवा लोगों पर किए गए शोध से हमें वयस्क समाज की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक चिंताओं के बारे में, उसकी सभी विविधताओं के बारे में, कम से कम बहुत कुछ पता चलता है, जैसा कि यह युवा लोगों के अपने जीवन के बारे में करता है। वास्तव में उनकी विविधता दोनों बहुत निकट से संबंधित हैं, और उन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है।" इसलिए इस संदर्भ में विकास का सटीक और वस्तुनिष्ठ आकलन प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया

जाएगा। ऐसा कहने के बाद, इस खंड में वैश्वीकरण के व्यापक आर्थिक प्रभाव और विशेष रूप से युवाओं पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव को उजागर करना सहायक हो सकता है।

वैश्वीकरण की चुनौतियाँ

वैश्वीकरण के कई लाभ हैं, लेकिन यह चुनौतियों से मुक्त नहीं है। वेलोसिटी ग्लोबल की 2020 स्टेट ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन रिपोर्ट: टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कुछ प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जिनका सामना अमेरिका और ब्रिटेन के प्रौद्योगिकी नेता अपनी कंपनियों को दुनिया भर में तैनात करते समय करते हैं, और अन्य कंपनियों के नेताओं को भी इसी तरह की बाधा का सामना करना पड़ सकता है।

आप्रवासन चुनौतियाँ और स्थानीय नौकरी का नुकसान : संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में राजनीतिक स्थिति वैश्वीकरण के प्रभावों पर अलग-अलग विचारों से चिह्नित है। दुनिया भर के कई देश अपने आप्रवासन कानूनों को लागू कर रहे हैं, और आप्रवासियों के लिए नए देशों में काम पाना मुश्किल है। राष्ट्रवाद में यह वृद्धि काफी हद तक इस बढ़ती धारणा के कारण है कि विदेशी लोग घरेलू कामों को पूरा कर रहे हैं या श्रम लागत को बचाने के लिए कंपनियों को बदल रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय रोजगार: सबसे पहले, राष्ट्र इस बारे में योजना बनाते हैं कि उम्मीदवारों से बातचीत कैसे की जाए और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मुख्यालय से हजारों मील दूर हैं। इसके बाद, देशों को वेतन की बाजार मांग और प्रतिस्पर्धी पेशकश करने के लाभों को जानने की आवश्यकता है। प्रभावी भर्ती सुनिश्चित करने के लिए, एचआर टीमों को कंपनी के लिए सही कंपनी खोजने के लिए समय क्षेत्र, सांस्कृतिक अंतर और भाषा सीमाओं जैसी चुनौतियों में भाग लेना चाहिए।

कर वृद्धि और निर्यात शुल्क: रिपोर्ट में यू.एस. और यू.के. के प्रौद्योगिकी नेताओं ने कहा कि उनके सामने एक और चुनौती मुद्रास्फीति और निर्यात लागत है - 29% सहमत हैं कि यह उनके वैश्विक व्यवसायों के लिए एक चुनौती है। विदेशों में उत्पाद बेचने की चाहत रखने वाली कंपनियों के लिए, उन वस्तुओं को विदेशों में खोजना महंगा हो सकता है, जो बाजार पर निर्भर करता है।

सांस्कृतिक स्वामित्व का नुकसान: हालाँकि वैश्वीकरण ने विदेशी देशों के लिए इसे एक्सेस करना आसान बना दिया है, लेकिन इसने विभिन्न समुदायों को फिर से एकजुट करना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में कुछ संस्कृतियों की सफलता ने कुछ देशों को समान आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन जब संस्कृतियाँ अपनी अनूठी विशेषताओं को खोने लगती हैं, तो हम अपनी वैश्विक विविधता खो देते हैं।

विदेशी श्रमिकों का शोषण: कम लागत से कई उपभोक्ताओं को लाभ होता है, लेकिन इससे कड़ी प्रतिस्पर्धा भी पैदा होती है जिसके कारण कुछ कंपनियाँ सस्ते श्रम संसाधनों की तलाश करती हैं। कुछ पश्चिमी कंपनियाँ अपने उत्पादों को चीन और मलेशिया जैसे देशों में निर्यात करती हैं, जहाँ ढीले कानून श्रमिकों का शोषण करना आसान बनाते हैं।

वैश्विक संचार चुनौतियाँ: मुख्यालय में परिचालन शुरू करने से पहले, फर्मों को आंतरिक संचार की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के अलग-अलग समय क्षेत्र में काम करने और उनकी मूल भाषा अलग होने की संभावना होती है। सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल उपकरण दुनिया भर में संचार बाधाओं को सुविधाजनक बनाते हैं और टीमों को अधिक आसानी से कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं। जूम, स्लैक और गूगल सभी

उन कंपनियों के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान करते हैं जो कई कार्यालयों, देशों और समय क्षेत्रों में कर्मचारियों का प्रबंधन करने का प्रयास करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों की अपेक्षाएँ: विदेशी कर्मचारी वेतन और लाभ जैसी चीज़ों के साथ-साथ अपने दैनिक कार्य शेड्यूल को प्रबंधित करने के तरीके के मामले में अलग-अलग चीज़ों की अपेक्षा करते हैं। वैश्वीकरण का लाभ उठाने और विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने वाली कंपनियों को यथासंभव ग्रहणशील होने की आवश्यकता है। एचआर टीमों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्ताव प्रतिस्पर्धी हो और नियुक्ति के समय स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा: अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को घरेलू प्रदर्शन से परे समायोजन करने की आवश्यकता है। दुनिया भर में जाने से राजस्व के नए स्रोत खुलते हैं और प्रतिभा की उपलब्धता बढ़ती है। इन आकर्षक लाभों के कारण, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय PEO जैसी सेवाओं के कारण दुनिया भर में आसान यात्रा के कारण, वैश्विक बाजार प्रतिस्पर्धी है। जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार एक चलन बनता जा रहा है, कई कंपनियाँ इसी तरह के विदेशी बाज़ार की तलाश करती हैं, जिससे व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।

अनुसंधान क्रियाविधि

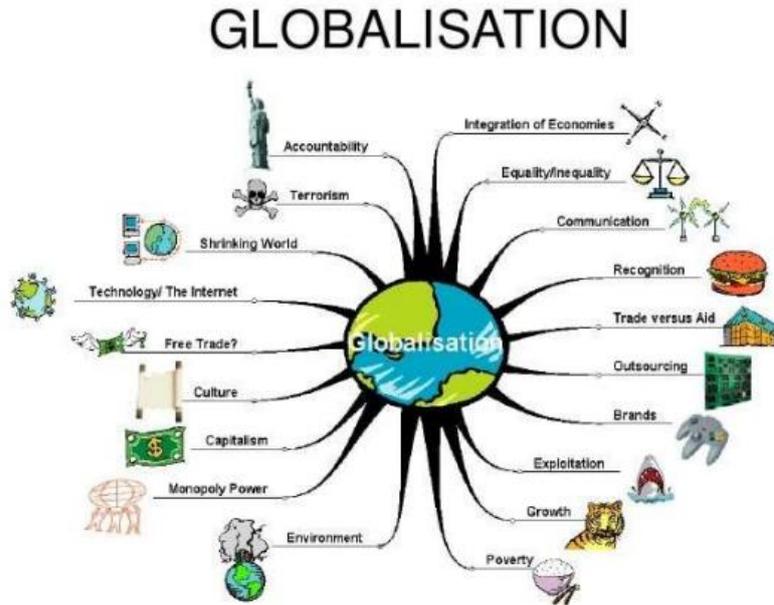
यह शोध आउटपुट वैश्वीकरण और भारत में इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, ग्रामीण भारत के विकास के अवसर, व्यापार और महामारी की स्थिति के दौरान भारतीय संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पर किए गए अवलोकन का परिणाम है, यह विश्लेषण के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग करता है, शोध कार्य के विशेषज्ञ भाग के साथ चर्चा करता है।

डेटा और सांख्यिकी

भारत के विभिन्न भागों में इंटरनेट उपयोगकर्ता या डिजिटल उपयोग

हम भारत में पिछड़े राज्यों या कम विकसित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कम पाते हैं, यहां तक कि ग्रामीण उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कार्यान्वयन और ग्राहकों को ऑनलाइन उत्पादों की आपूर्ति करना अधिक कठिन लगता है, उदाहरण के लिए: ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आतिथ्य, होटल सेवाएं और शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करना।

वैश्वीकरण के मुख्य बिंदु



ग्राफ में वैश्वीकरण के आवश्यक तत्वों को दर्शाया गया है, जैसे प्रौद्योगिकी, साक्षरता स्तर, पूंजी तथा भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव जैसे बाजारों में प्रतिस्पर्धा के स्तर में वृद्धि, ग्रामीण और शहरी उत्पादों के ब्रांडों में वृद्धि, ग्रामीण और शहरी भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अधिक भूमिका।

परिणाम और चर्चा

परिणाम भारतीय राज्यों, या भारतीय ग्रामीण उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव को समझाता है, भारत के ग्रामीण भागों में ग्रामीण उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्याओं और भारत में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों द्वारा लचीली राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू किया जाना है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के कारण भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जरूरतमंदों को नौकरी उपलब्ध कराने में बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, बेरोजगारी के कारण, हम गरीबी से पीड़ित आबादी का बड़ा हिस्सा पा सकते हैं, उदाहरण के लिए: बिहार और यूपी (उत्तर प्रदेश में गरीबी का बड़ा हिस्सा है, इसके अलावा इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने वाले उद्यमियों की संख्या कम है, यही मुख्य कारण है कि वैश्वीकरण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ाकर दीर्घावधि में राज्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है, दुनिया की अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों में डिजिटल कार्यान्वयन द्वारा श्रम की तुलना में प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग कर रही हैं, 20वीं सदी के बाद हमने देखा है कि लाभ या आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र के उद्यमियों को बेचा जाता है, लेकिन इससे भारत में स्थानीय या घरेलू कंपनियों के लिए अपने उत्पाद बेचना भी मुश्किल हो सकता है।

संदर्भ

1. लाल बी. सुरेश, वैश्वीकरण के युग में बंजारों के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: तेलंगाना जनजातीय गांवों में एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज (आईजेपीएसएस), खंड-5, अंक-6, जून, 2015 पृ.195-211.
2. टीडब्ल्यूडी, तेलंगाना में जनजातीय कल्याण क्षेत्र की चुनौतियाँ, तेलंगाना सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग, हैदराबाद, 2019।
3. लाल बी. सुरेश, एचआईवी/एड्स का आर्थिक प्रभाव: आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में एक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट स्टडीज: एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, खंड 5, संख्या 1-2, जनवरी और जून, 2010, पृ. 139-146.
4. लाल बी. सुरेश, मधुमेह: कारण, लक्षण और उपचार। लाल बी.एस. (संपादक)। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे, धारावाहिक प्रकाशन, 2016, नई दिल्ली।
5. एलन जे और डी. मैसी, भौगोलिक दुनिया (ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019)।
6. फर्लांग और एफ. कार्टमेल, उद्धृत; और यू. बेक, रिस्क सोसाइटी: टुवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी (लंदन, सेज, 2019)।
7. गिडेंस, आधुनिकता और आत्म-पहचान: आधुनिक युग में स्वयं और समाज (कैम्ब्रिज, पॉलिटी प्रेस, 2019), पृष्ठ. 64.
8. ग्रिफिन सी, "युवाओं की एक नई कहानी की कल्पना: युवा शोध, 'नया यूरोप' और वैश्विक युवा संस्कृति"...., पृष्ठ 149।
9. केली पी, "जंगली और पालतू क्षेत्र: जोखिम में युवाओं के संक्रमण को विनियमित करना", जर्नल ऑफ यूथ स्टडीज, खंड 2, संख्या 2 (2018), पृष्ठ 193-211।
10. माइल्स एस, उद्धृत; और सी. ग्रिफिन, "युवाओं की एक नई कहानी की कल्पना: युवा अनुसंधान, नया यूरोप और वैश्विक युवा संस्कृति"
11. रॉबर्ट्स के, "पूर्व साम्यवादी देशों में स्कूल से काम में बदलाव", जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड वर्क, खंड 11, संख्या 3 (2018), पृष्ठ 234।
12. संयुक्त राष्ट्र (2017): युवाओं के लिए विश्व कार्य कार्यक्रम (डब्ल्यूपीएवाई)।
13. संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (यूएनडीईएसए) रिपोर्ट 2021: युवा और प्रवासन।
14. विश्व युवा रिपोर्ट (2021): एशियाई युवाओं में तेजी से वैश्वीकरण।
15. किंगडन, जी. (2017)। भारत में स्कूली शिक्षा की प्रगति। बी. स्टीवन, विंसेंट ए. अनफारा और आर. कैथलीन (संपादक), युवा किशोरों को शिक्षित करने पर एक अंतरराष्ट्रीय नज़र (पृष्ठ 90-100)। न्यूयॉर्क: सूचना आयु प्रकाशन।

16. किरमायर , एल.जे., और मिनास, आई.एच. (2020)। सांस्कृतिक मनोरोग का भविष्य: एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। कैनेडियन जर्नल ऑफ़ साइकियाट्री, 45, 438–46।
17. कुनिट्ज़ , एस.जे. (2020)। वैश्वीकरण , राज्य और स्वदेशी लोगों का स्वास्थ्य। अमेरिकन जर्नल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, 90, 1531–9
18. कुरियन , एनजे (2017)। आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का बढ़ना: भारत के लिए निहितार्थ। इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च, 126, 374–80।